मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) (क) जी, हां।

(ख) देश भर में थियेटर संबंधी गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमें और कार्यक्रम पहले से मौजूद हैं। थियेटर संगठनों को अनुदान प्राप्त करने के अतिरिक्त, संगीत नाटक अकादेमी निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रही हैं:

(i) युवा थियेटर कर्मियों को सहायता।

(ii) भारतीय भाषाओं में नाटककार कार्यशालायें।

(iii) युवा थियेटर निर्देशकों के लिए कार्यशालाप।

(iv) युवा निर्देशकों द्वारा निर्देशित नाटकों को प्रायोजित करना।

इसके अलावा, संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र नियमित रूप से थियेटर महोत्सवों और कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा व्यावसायिक तथा शौकिया थियेटरों समूहों को सहायता प्रदान करते हैं।

संस्कृति विभाग एक स्कीम भी संचालित करता है, जिसके अंतर्गत थियेटर समूहों तथा स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को वेतन अनुदान और प्रस्तुति अनुदान प्रदान किया जाता है।

ASI as a scientific department

1298. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Archaeological Survey of India has been declared as a scientific department, but the implementation of the same has not been done so far; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) Yes Sir. The Archaeological Survey of India has been declared as Science and Technology Organisation. Consequent upon declaration as Science and Technology Organisation, the Survey has already been exempted from the purview of Director General Supplies and Disposal and Staff Inspection Unit of Ministry of Finance. Certain other matters have also been taken up with the concerned Departments of Government.

(b) Does not arise

Organisation of Security wing by ASI

1299. SHRI GAYA SINGH: Will the Minsiter of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that despite a report on Security of National Monuments and Museums by Lt. Col. J.S. Marwah, Officer on Special Duty in 1974 and similar recommendations of Mirdha Committee on Archaeology in 1983, the security wing has not been organised in the Archaeological Survey of India till date; and

(b) if so, the reasons thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) No, Sir. Some of the recommendations of Lt. Col. J.S. Marwah, Officer on Special Duty and Mirdha Committee on Security aspects of Monuments/Museums under Archaeological Survey of India have already been implemented. However creation of separate security force was not found feasible. Instead armed Police personnel are engaged for the safety of important Museums.

(b) Does not arise.

सिंचाई जल दरों का पुनरीक्षण

1300. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मई, 1995 के "स्टेट्समैन" में "रिवीजन ऑफ इरीगेशन वाटर रेट्स स्ट्रेस्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सिंचाई से प्राप्त होने वाला राजस्व इस पर होने वाले व्यय की तुलना में बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो औसतन देश में प्रति हेक्टेयर राजस्व की प्राप्ति की मात्रा तथा प्रति हेक्टेयर सिंचाई व्यवस्था पर होने वाले व्यय की मात्रा क्या-क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्राप्तियों को व्यय के बराबर लाने के लिए कोई कारगर कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) योजना आयोग को सितम्बर, 1992 में प्रस्तुत की गई सिंचाई जल का मूल्य निर्धारण संबंधी समिति (जो वैद्यनाथन समिति के नाम से जानी जाती है) की रिपोर्ट के अनुसार, 1989-90 में औसतन वास्तविक सिंचाई राजस्व 50 रुपये प्रति हेक्टेयर आया है जबकि प्रचालन और अनुरक्षण लागत 270 रुपये प्रति हेक्टेयर आयी है। वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों का अध्ययन योजना आयोग द्वारा दिसंबर, 1992 में गठित किए गए अधिकारियों के दल द्वारा किया गया था। अधिकारियों के दल ने दिसम्बर 1994 की अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि विद्यामन सिंचाई जल दरों में संशोधन किया जाये जिससे फेजवार अर्थात अगले पांच वर्षों में वार्षिक प्रचालन व अनुरक्षण की पूरी लागत वसूल की जा सके। सिंचाई राज्यों का विषय है अतः वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट के साथ अधिकारियों के दल की सिफारिशों को विचार और आगे की कार्यवाई के लिए योजना आयोग द्वारा सभी राज्यों के भेजा गया है।

National Conference of Principals of Kendriya Vidyalayas

1301. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a 3 day National Conference of the Principals of Kendriya Vidyalayas was held in the capital starting on June 30, 1995 to evolve ways and means to strengthen primary education and explore emerging trends in educational technology;

(b) if so, what were the precise suggestions and observations made therein and the strategy for universalisation of primary education; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION & DEPTT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (c) As per information provided by the Kendriya Vidyalaya Sangathen, a three-day National Conference of the Principals of Kendriya Vidyalayas was held in the Capital from June 30, 1995. The Conference observed that activity based teaching should be introduced in primary classes, with emphesis on competency development. Kendriya Vidyalaya Sangathan has taken steps for introduction of activity bases teaching in primary classes.

Housing Activities During the Eight Plan

1302. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have formulated comprehensive action plan for massive housing activities for lower and middle income-groups during the Eighth Plan period;

(b) if so, the details thereof, State-wise; and

(c) the schemes for providing shelter to homeless and achievements made so far, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) to (c) The following Central Sector schemes are in operation during Eighth Plan:—

(i) SHELTER UPGRADATION UNDER NEHRU ROZGAR YOJANA:—

The Scheme envisages Central and State Govt. subsidy @ Rs. 1000/- in the